only to acquaint himself with the progress of the programmes, but also to assist the States in solving difficulties, if any, experienced by them.

उड़ीसा को चावल का सम्भरण

११७. श्री किशन पटनायक : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उड़ीसा में खाद्याभाव की पूर्ति के लिए अभी तक कितना चावल भेजा जा चुका है ;

(ख) यह परिमाण कब उड़ीसा पहुंचा है ; और

(ग) कितना भेजना बाकी है, और कब भेजा जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग) एक सामान्य वर्ष में उड़ीसा राज्य में चावल की उपज वहां की आवश्यकता से अधिक होती है और १९६१ तथा १९६२ के वर्षों में तीन लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल और धान (चावल के बराबर) उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल को व्यापारियों द्वारा भेजा गया। इस वर्ष उड़ीसा में चावल की उपज कुछ कम हुई है। इस वर्ष उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल को चावल और धान का निर्यात पिछले वर्षों की इसी अवधि की अपेक्षा काफी कम रहा है। १ जनवरी, १९६३ से केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को कुल ४२ हजार मीट्रिक टन चावल देना स्वीकार किया है। २१ जुलाई तक उनके पास लगभग ३६ हजार मीट्रिक टन पहुंच चुका था। बाकी मात्रा या तो भेजी जा रही है या मार्ग में है।

दिल्ली में यमुना पर नाव का पुल

११८. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री २६ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान रेलवे पुल के निकट नावों का जो अस्थायी पुल बनाया गया था बरसात में [illegible] तोड़े जाने के बाद यातायात के निकास के [illegible] व्यवस्था की गई है ; और

(ख) क्या बरसात के बाद नावों के उस स्थायी पुल का फिर से निर्माण करने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सूखे मौसम में जब नदी में बाढ़ नहीं होती रेल और सड़क के मिले जुले पुल में यातायात की भीड़ कम करने के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में नावों का पुल बनाया गया था। नावों के अस्थायी पुल को तोड़ने के बाद कोई दूसरी व्यवस्था सम्भव नहीं है। सारा यातायात मौजूदा रेल और सड़क के मिले जुले पुल द्वारा होता है।

(ख) जी, हां।

Typists in the Railways

119. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the recommendations of the Second Pay Commission regarding merger of Typists with clerical category in Railways has been turned down by the Railway Board;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what is the incentive given to them like Stenographers?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes, Sir.

(b) It was decided to keep the Typists cadre separate for administrative reasons.

(c) No incentive is given to the Typists.